2 .89 करोड़ वोटरों के नाम कटे

यूपी में मतदाता सूची में बड़ा संशोधन, चुनाव आयोग ने जारी की ड्राफ्ट लिस्ट

लखनऊ, 6 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है.

इस प्रक्रिया में राज्य से 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिससे कुल मतदाता संख्या में करीब 18.70 प्रतिशत की कमी आई है. आयोग के अनुसार यह कदम मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी. इस संशोधन के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12.56 करोड़ रह गई है. यानी करीब 2.89 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 18.70 प्रतिशत है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि एसआईआर के दौरान ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई जिनका सत्यापन नहीं हो सका था. आंकड़ों के अनुसार, हटाए गए 2.89 करोड़ मतदाताओं में से 1.29 करोड़ को स्थायी रूप से स्थानांतरित, 46 लाख को मृत, 25.4 लाख को डुप्लीकेट और 79.5 लाख को लापता की श्रेणी में रखा गया है. इसके अलावा 7.74 लाख मतदाताओं ने बूथ-स्तरीय अधिकारियों से फॉर्म लेने के बावजूद सत्यापन फॉर्म वापस नहीं किए.

> मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संसद में विकसित भारत को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पारित किया जी राम जी योजना देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल के लिए वह पीएम का हृदय से अभिनंदन करते हैं. जिन लोगों ने वर्षों तक संसाधनों पर डकैती डालकर देश को बेरोजगारी की ओर धकेला, आज उन्हें अपनी पोल खुलने का डर सता रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को वेतन समानता की मांग की अनुमति दी

नई दिल्ली, 06 जनवरी. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कुछ अल्पकालिक (पार्ट-टाइम) शिक्षकों को यह अनुमति दी कि वे राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के समक्ष नया प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें, जिसमें वे गैर-सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पूर्ण-कालिक शिक्षकों के समान वेतन (वेतन समानता) की मांग कर सकें। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने निर्देश दिया कि यदि यह प्रतिवेदन दाखिल किया जाता है, तो उस पर कानून के अनुसार विचार किया जाए.

नेपाल में फिर हिंसा, भारतीय सीमा सील

- मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद पारसा-धनुषा में तनाव

नई दिल्ली, 06 जनवरी. पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है, जिसका असर सीधे भारत-नेपाल सीमा तक देखने को मिल रहा है.

मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना के बाद नेपाल के पारसा और धनुषा जिलों में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सीमा सील कर दी गई है और सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. नेपाल के भारतीय सीमा से सटे इलाकों में एक बार फिर हिंसा ने चिंता बढ़ा दी है. नेपाल के पारसा और धनुषा जिलों में सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. हालात बिगड़ते देख सुरक्षा कारणों से भारत-नेपाल अंतरर्राष्ट्रीय सीमा को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है. नेपाल पुलिस के अनुसार, धनुषा जिले के सखुवा मारान क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद में तोड़-फोड़ की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद माहौल और भड़क गया. वीडियो के प्रसार के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और नफरत फैलाने वाली टिप्पणियां सामने आईं, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव गहराता चला गया. इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

श्रम कानूनों के अमल को राष्ट्रपति की मंजूरी

- उपराज्यपालों और प्रशासकों को मिले व्यापक अधिकार

नई दिल्ली 6 जनवरी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सभी केन्द्र शासित प्रदेशों में नये श्रम कानूनों को पारदर्शिता के साथ लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए उप राज्यपालों तथा प्रशासकों को सरकारों के अनुरूप अधिकारों का निर्वहन करने की अनुमति दे दी है.

ये अधिकार औद्योगिक संबंध संहिता 2020 तथा संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबंध (1) के अनुरूप हैं और 16 जनवरी 2023 तथा 22 जून 2023 की जगह लेंगे. गृह मंत्रालय ने दो जनवरी को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि नयी अधिसूचना से पहले जारी अधिसूचना के तहत लिए गये निर्णय प्रभावित नहीं होंगे.

अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर के प्रशासक या उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अंतर्गत उन क्षेत्रों के लिए, जहां संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के रूप में कार्य करना अपेक्षित है, उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.

जानकारों का कहना है कि उप राज्यपालों और प्रशासकों को ये अधिकार इसलिए दिये गये हैं जिससे कि श्रम सुधारों को पूरी तरह लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आये. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार श्रम कानूनों के प्रभावी अमल के लिए स्पष्ट प्रशासनिक अधिकार होना जरूरी हैं जिससे कि किसी संदेह या विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी जल्द निर्णय ले सकें.

जापान में 6 .2 तीव्रता का आया भूकंप

टोक्यो, 06 जनवरी. जापान के पश्चिमी चुगोकू क्षेत्र के शिमाने प्रांत में मंगलवार को भूकंप के कई झटके महसूस किये गये. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गयी, हालांकि सुनामी का कोई खतरा नहीं है. गौरतलब है कि भूकंप के केंद्र से मात्र 32 किमी दूरी पर 'शिमाने परमाणु ऊर्जा केंद्र' है. जापान के परमाणु नियामक प्राधिकरण ने कहा कि संयंत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं पायी गयी है. एक प्रवक्ता ने बताया कि संयंत्र का संचालन करने वाली चुगोकू इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र की इकाई दो पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की जा रही है. यह इकाई मार्च 2011 में फुकुशिमा आपदा के बाद बंद कर दी गयी थी.

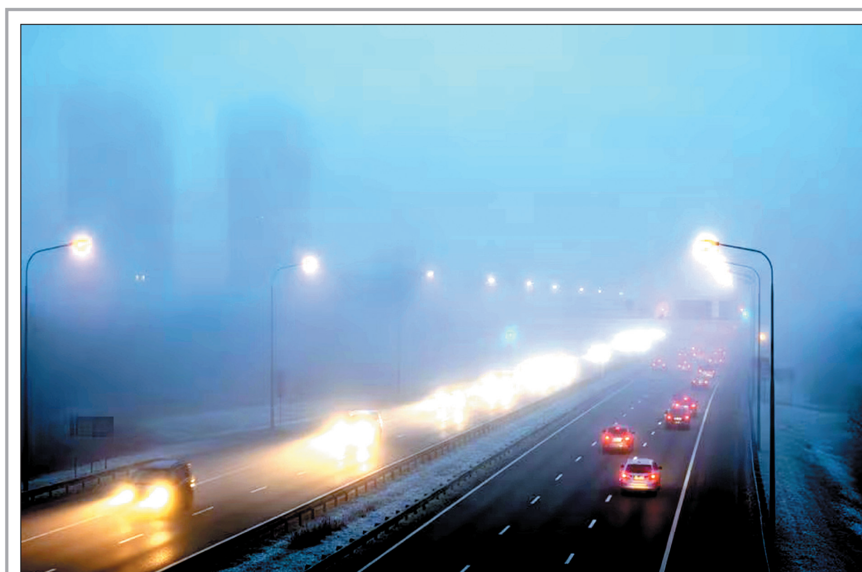

घने कोहरे की चादर

पटना, 06 जनवरी. बिहार के कई जिलों में तापमान तेजी से गिरने के साथ ही शीतलहर का असर और तेज हो गया है, वहीं पश्चिम चंपारण, लखनऊ गयाजी समेत कई जिले घने कोहरे की चादर में लिपटे रहे, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई.

मेरी टिप्पणियों को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया : पवार

मुंबई, 06 जनवरी. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) पर उनकी हालिया टिप्पणियों को मीडिया मे गलत तरीके से पेश किया था जबकि उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था. श्री अजीत पवार ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, मीडिया ने मेरे बयान को अलग तरह से पेश किया. मैंने आरोप नहीं लगाया था. महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है. मैंने यही कहा था लेकिन मेरा पूरा बयान नहीं दिखाया गया.

एक नजर में

घने कोहरे से 280 से अधिक उड़ानों में देरी

नई दिल्ली, 06 जनवरी. राष्ट्रीय राजधानी और देश के दूसरे हिस्सों में मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 280 से अधिक उड़ानों में देरी की सूचना है और कुछ उड़ानें रद्द हैं. दिल्ली हवाई अड्डे पर सुबह चार बजे के बाद दृश्यता घटने लगी और 150 मीटर तक गिर गयी. चार बजे के बाद से ही कैट-3 प्रक्रिया के तहत उपकरण की मदद से परिचालन शुरू कर दिया गया. अमृतसर, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, वाराणसी, रांची, हिंडन (गाजियाबाद) और धर्मशाला में भी दृश्यता कम होने के कारण उड़ानों के परिचालन में देरी हो रही है. दिल्ली हवाई अड्डे की वेवसाइट के अनुसार, आज दिल्ली से जाने वाली कम से कम 20 और दिल्ली आने वाली कम से कम 260 उड़ानों में देरी की सूचना है. कैट-3 की प्रक्रिया के तहत रनवे के साथ-साथ विमान का भी कैट-3 उपकरण से लैस होना जरूरी है. पायलट भी कैट-3 में लैंडिंग और टेकऑफ के लिए प्रशिक्षित होना चाहिये.

नाबालिग से दुष्कर्म हत्या के दोषी को फांसी

कटक, 06 जनवरी. बच्चों के खिलाफ बढ़ते जघन्य अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए ओडिशा हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की जीत है, बल्कि समाज को यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि ऐसे अमानवीय अपराधों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. अदालत ने इसे 'दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में रखा. ओडिशा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. यह मामला राज्य के तटीय क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है, जहां दो वर्ष पहले 12 वर्षीय बच्ची रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी. बाद में उसका शव जंगल से बरामद किया गया, जिस पर गंभीर हिंसा के स्पष्ट निशान पाए गए थे. जांच के दौरान पुलिस ने उसी इलाके में रहने वाले एक मजदूर को गिरफ्तार किया. 18 महीने तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज, डीएनए जांच, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और प्रत्यक्ष गवाहों के बयानों के जरिए आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए. अदालत ने सभी साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए दोष सिद्ध किया.

भारत-यूएई के बीच रक्षा सहयोग जरूरी

नई दिल्ली, 6 जनवरी. सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के बीच मजबूत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रक्षा सहयोग पर बल दिया है. सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यूएई की यात्रा पर गये जनरल द्विवेदी ने मंगलवार को नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) के अधिकारियों को संबोधित किया. उन्होंने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में हो रहे बदलावों और आधुनिक संघर्षों के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डाला तथा आधुनिक युद्ध में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया. सेना प्रमुख ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की नेतृत्वकारी भूमिका पर जोर दिया और सहयोगात्मक साझेदारियों महत्व का उल्लेख किया. उन्होंने भारत, यूएई और अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के बीच मजबूत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा सहयोग को आवश्यक बताया. उन्होंने कहा कि परस्पर लाभ के लिए ये जरूरी हैं और इनसे क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान सकारात्मक सैन्य सहभागिता को और मजबूत करने, प्रशिक्षण में समन्वय बढ़ाने तथा भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई.

भारत-लक्जमबर्ग के संबंधों होंगे और मजबूत

- जयशंकर-लक्जमबर्ग पीएम की अहम मुलाकात
- नवाचार और वित्तीय सेवाओं पर फोकस

नई दिल्ली, 06 जनवरी. लक्जमबर्ग की यात्रा पर गये विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन से मुलाकात की और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत की.

मुलाकात के बाद डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा सुबह लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन से मिलकर प्रसन्नता हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित कीं. वित्तीय सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा हुई. भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को और सशक्त बनाने के लिए उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उल्लेखनीय है कि डॉ. जयशंकर रविवार को फ्रांस और लक्ज़मबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए थे.

पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों की केजरीवाल ने सराहना की

नई दिल्ली, 06 जनवरी. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली, के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार की स्वास्थ्य पहल की सराहना की है.

उन्होंने पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को दी जा रही सेवाओं को जनकेंद्रित शासन का उदाहरण बताया. केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों में हर महीने 20,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण और नि:शुल्क प्रसवपूर्व देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाएं घर-घर तक पहुंच रही हैं, जिससे हर मां को सम्मान, सुरक्षा और समय पर इलाज सुनिश्चित हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित कर रहा है, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है.

आज का इतिहास

- 1851 – प्रसिद्ध इतिहासकार, अंग्रेज़ी साहित्यकार तथा अन्वेषक जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जन्म.
- 1859 – अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने सिपाही विद्रोह में शामिल होने के आरोप में मुकदमा शुरू किया.
- 1893 – गांधीवादी जीवन शैली की कट्टर समर्थक जानकी देवी बजाज का जन्म.
- 1943 – मशहूर अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला का निधन.
- 1950 – अंतरर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बालश्रम विरोधी कार्यकर्ता शांता सिन्हा का जन्म.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन

पुणे, 06 जनवरी. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कलमाड़ी का मंगलवार को पुणे के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 81 साल के थे. पुणे के पूर्व सांसद और राजनीति एवं खेल जगत में एक जानी-मानी हस्ती श्री कलमाड़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां, बेटा और पोते-पोतियां हैं. कई वरिष्ठ राजनीतिक नेता, पार्टी के साथी और समर्थक उनकी निधन की खबर सुनकर उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय छाजेड ने कहा कि श्री कलमाडी के निधन से पुणे के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में दुख की लहर दौड़ गई है.

कांग्रेस ने अंकिता मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की

नई दिल्ली, 06 जनवरी. अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में रोष के बीच कांग्रेस ने मामले की पूरी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है, जिससे उसे न्याय मिल सके और सच सबके सामने आ सके.

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पहाड़ की एक बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ. उस बेटी के ऊपर जिस्मफरोशी का दबाव बनाया गया और जब उसने मना कर दिया तो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई. वहीं, इस मामले में सारे सबूत छिपाने के लिए तुरंत उस होटल पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि उसमें भाजपा के नेता का बेटा शामिल था. उन्होंने कहा कि ऐसी बातें सामने आ रही है कि यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचता है. पूरे उत्तराखंड के साथ ही भाजपा के लोग भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं.

उत्तराखंड की सरकार अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दे सकती, क्योंकि ये सरकार चैन की नींद सो रही है. कांग्रेस प्रवक्ता ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए कहा कि अंकिता को हर कीमत पर न्याय मिलना चाहिए और ये तभी होगा जब सीबीआई इसकी जांच करेगी.

एसआईटी ने सभी पहलुओं पर जांच की : धामी

अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीएम ने दी प्रतिक्रिया

देहरादून, 6 दिसंबर. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हाल ही में जारी एक ऑडियो की सत्यता को जानने के लिए एसआईटी का गठन कर लिया गया है.

उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड मे सामने आए घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंकिता की हत्या एक संवेदनशील और हृदय विधायक घटना थी, और इस घटना से हम सब बहुत आहत हुए. उन्होंने कहा कि जब यह घटना घटी थी, उस दौरान भी वो राज्य के मुख्य सेवक थे, जैसे ही उनको इस घटना की जानकारी मिली तभी उन्होंने पुलिस और प्रशासन को आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश जारी कर दिये थे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जिस स्थान पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था वहां से अंकिता के शव को भी बरामद कर लिया था. इस प्रकरण में एक महिला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी जांच गठित की गई.

> एसआईटी ने हर पहलूओं पर जांच की, जिन लोगों को इस केस के बारे में जो भी जानकारियां थी,एसआईटी उन सभी लोगों से मिली, सरकार की तरफ से संचार के माध्यम से यह भी प्रचारित किया कि इस घटना से जुड़े तथ्य यदि किसी के पास हैं, तो उसे एसआईटी को उपलब्ध करवाये. श्री धामी ने कहा कि इस प्रकरण में लगातार कार्रवाई चलती रही और सरकार की मजबूत पैरवी के परिणाम स्वरूप तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई. उन्होंने कहा कि अब एक ऑडियो का प्रकरण सामने आया है. इस ऑडियो की सत्यता जानने के लिए एसआईटी का गठन किया.

सुविधा पश्चिम रेलवे ने डिजिटल टिकट पर 3 फीसदी कैशबैक योजना शुरू की

रेलवन ऐप से टिकटिंग को बढ़ावा

मुंबई, 06 जनवरी. पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों को रेलवन ऐप के माध्यम से डिजिटल, त्वरित एवं कैशलेस टिकटिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक व्यापक जन-जागरूकता एवं प्रचार अभियान शुरू किया गया है.

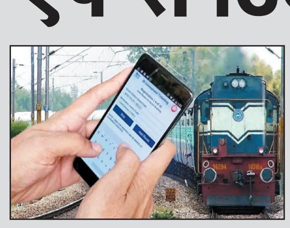

इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और यात्रा को अधिक सुगम बनाना है. रेलवन ऐप एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यात्री आरक्षित टिकट बुकिंग, अनारक्षित टिकट बुकिंग एवं प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेनों की रियल टाइम जानकारी, ग्राहक सहायता आदि जैसी रेलवे की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टिकट बुकिंग स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ तथा संबंधित पर्यवेक्षकों को रेलवन ऐप की विशेषताओं के बारे में संवेदनशील किया गया है, ताकि वे यात्रियों को प्रभावी रूप से मार्गदर्शन एवं प्रेरित कर सकें. वाणिज्यिक पर्यवेक्षक एवं टिकट चेकिंग स्टाफ स्टेशनों पर सक्रिय रूप से प्रचार अभियान चला रहे हैं, जिनके माध्यम से ऐप की उपयोगिता एवं सरलता को उजागर किया जा रहा है. सार्वजनिक जागरूकता को और अधिक बढ़ाने के लिए स्टेशनों पर पोस्टर एवं पर्चे प्रदर्शित एवं वितरित किए जा रहे हैं, प्रमुख स्टेशनों पर विशेष सहायता काउंटर स्थापित किए गए हैं.

> वर्तमान में यूटीएस ऐप का उपयोग कर रहे यात्रियों को भारतीय रेल के ऑल-इन-वन मोबाइल एप्लिकेशन रेलवन पर सहज रूप से स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे एक ही उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग जारी रखने के साथ-साथ अनेक अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठा सकें. मौजूदा यूटीएस उपयोगकर्ता प्रदान किए गए इमेज फ्लोचार्ट में दर्शाई गई.

गडकरी ने की झारखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा

परियोजनाओं की प्रगति से जुड़ी जानकारी ली

नई दिल्ली, 06 जनवरी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं की सोमवार को समीक्षा की. मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड में 18,214 करोड़ रुपए की लागत से 687 किमी लंबी परियोजनाओं पर काम चल रहा है.

केंद्रीय मंत्री इन परियोजनाओं की प्रगति से जुड़ी जानकारी के बारे में अपने सहयोगी मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. सूत्रों के अनुसार बैठक नीतीन गडकरी के कार्यालय में हुई जिसमें झारखंड में चल रही 20 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक में मंत्रालय में राज्यमंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा के साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे.